27 SEP 20

दैनिक भास्कर, जयपुर

दैनिक भास्कर, जयपुर

भास्कर खास • समय रहते हुए टेंडर जारी नहीं हुआ तो केंद्र सरकार से मिल रही 150 बसों भी छूट जाएगी हाथ से

गडकरी ने कहा- दो साल में देश में सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक
रोडवेज प्रशासन- छह माह में 2 इलेक्ट्रिक बसें भी नहीं खरीदी

नरेश वशिष्ठ | जयपुर

पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ावा देने और पॉल्यूशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली सहित अन्य शहरों में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल 23 अगस्त को 64 शहरों को 5500 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चार दिन पहले ही कहा है कि 'आने वाले दो साल में सभी बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।' इसके बाद भी प्रदेश के रोडवेज प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार जहां दो साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात कह रहा है। वहीं रोडवेज प्रशासन 6 माह में 2 इलेक्ट्रिक बसें भी नहीं खरीद पाया। कांग्रेस सरकार आने के बाद रोडवेज प्रशासन ने जयपुर दिल्ली मार्ग पर शुरूआत में दो इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 2 बसों की खरीद करनी थी, लेकिन अभी तक ये बसें फाइलों से उतर कर सड़क पर नहीं दौड़ पाई। रोडवेज के पास वर्तमान में करीब 4 हजार 500 बसें हैं। खरीद की रफ्तार यही रही तो 4 हजार 500 बसों को इलेक्ट्रिक में तबदील करने में लग जाएंगे वर्षों।

गडकरी ने कहा, 'ये गाडियां बायो-सीएनजी, एथनॉल, मेथनॉल पर चलेंगी।' उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनिवार्य किए बिना ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने लिए जोर दिया। बदलाव सरकार द्वारा स्वच्छ इंधन अपनाने के लिए कोई जोर-जबर्दस्ती किए बिना होगा।

केंद्र से मिली 150 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तक नहीं बनाए

केंद्र सरकार ने फेम-2 स्कीम के तहत राज्य को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। इन बसों के लिए नवम्बर माह टेंडर करना है। केंद्र सरकार की लॉटरी निकलने के दो माह बाद भी रोडवेज और जेसीटीएसएल ने टेंडर डॉक्यूमेंट तक तैयार नहीं किया है। समय रहते टेंडर नहीं निकाला तो केंद्र से स्कीम के तहत मिली इलेक्ट्रिक बसें भी छूट जाएंगी।

यह है केंद्र की स्कीम

केंद्र सरकार बसों की खरीदारी में राज्य को पैसा देगी। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए केंद्र ने 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

केंद्र से मिली बसों की टेंडर प्रक्रिया नवम्बर तक पूरी करनी थी। टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अभी टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ है। नए एमडी को मैंने पूरी जानकारी दे दी है।

- शुचि शर्मा, पूर्व एमडी रोडवेज